

बाँध सुरक्षा वधियक, 2019

प्रलिस के लयि:

केंद्रीय जल आयोग, बाँध सुरक्षा वधियक, 2019, राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधकिरण

मेन्स के लयि:

बाँध सुरक्षा वधियक, 2019 की प्रमुख वशिषताएँ, इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद ने देश भर में सभी नरिदषिट बाँधों की नगिरानी, नरीकषण, परचालन और रखरखाव के लयि **बाँध सुरक्षा वधियक, 2019** को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बदि

■ वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समति:** वधियक राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समति की स्थापना का प्रावधान करता है। समति की अधयकषत **केंद्रीय जल आयोग** के अधयकष द्वारा की जाएगी।
 - **समति के कार्यों** में बाँध सुरक्षा मानदंडों से संबंधति नीतयिँ एवं वनियम बनाना तथा बाँधों को कषतगिरसत होने से रोकना एवं बड़े बाँधों के टूटने के कारणों का वशिषण करना एवं बाँध सुरक्षा प्रणालयिँ में बदलाव का सुझाव देना शामिल होगा।
- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधकिरण:** वधियक एक **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधकिरण (National Dam Safety Authority -NDSA)** की स्थापना का प्रावधान करता है। इस प्राधकिरण का प्रमुख एडशिनल सेक्रेटरी से नीचे के स्तर का अधकिारी नहीं होगा एवं इसे केंद्र सरकार द्वारा नयिकृत कयिा जाएगा।
 - **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधकिरण** के मुख्य कार्य में **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समति** द्वारा नरिमति नीतयिँ को लागू करना शामिल है। राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) के बीच और SDSOs एवं उस राज्य के कसी बाँध मालकि के बीच वविादों को सुलझाना, बाँधों के नरीकषण और जाँच के लयि वनियम को नरिदषिट करना।
 - NDSA बाँधों के नरिमाण, डज़िाइन तथा उनमें परविरतन पर काम करने वाली एजेंसयिँ को मान्यता (Accreditation) देगी।
- **राज्य बाँध सुरक्षा संगठन:** प्रस्तावति कानून में राज्य सरकारों द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (State Dam Safety Organisation- SDSOs) की स्थापना की जाएगी जसिका कार्य बाँधों की नरितर चौकसी एवं नरीकषण करना तथा उनके परचालन एवं रखरखाव पर नगिरानी रखना, सभी बाँधों का डेटाबेस रखना और बाँध मालकिों को सुरक्षा उपायों की सफिरशि करना होगा।
- **बाँध मालकिों की दायतिव:** वधियक में नरिदषिट बाँध मालकिों से यह अपेक्षा की गई है कि वे **प्रत्येक बाँध के लयि एक सुरक्षा इकाई** स्थापति करे। यह इकाई मानसून सत्र से पहले और बाद में एवं प्रत्येक भूकंप, बाढ़, या कसी अन्य आपदा या संकट के संकेत के दौरान और बाद में बाँधों का नरीकषण करेगी।
 - बाँध मालकिों से **एक आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करने** और प्रत्येक बाँध के लयि **नरिदषिट अंतराल पर नयिमति जोखमि आकलन करने की अपेक्षा** की जाएगी।
 - बाँध मालकिों द्वारा नयिमति अंतराल पर एक वशिषज्ज पैनल के जरयि प्रत्येक बाँध का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन कयिा जाएगा।
- **सज़ा:** वधियक में **दो प्रकार के अपराधों** का उल्लेख है- कसी वयकर्ता को उसके कार्यों के नरिवहन में बाधा डालना और प्रस्तावति कानून के अंतरगत जारी नरिदेशों के अनुपालन से इनकार करना।
 - अपराधयिँ को **एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडति कयिा जाएगा।** अगर अपराध के कारण कसी की मृत्यु हो जाती है तो कारावास की अवधि दो वर्ष हो सकती है।
 - अपराध संज्जेय तभी होंगे जब **शकियत सरकार द्वारा या वधियक के अंतरगत गटति कसी प्राधकिरण** द्वारा की जाए।

■ आवश्यकता

○ बाँधों का कालकि कषय:

- बाँधों की संख्या के मामले में भारत वशि्व में तीसरे स्थान पर है। देश में 5,745 जलाशय हैं जनिमें से 293 जलाशय 100 साल से अधकि पुराने हैं। बाँध सुरक्षा के लयि कई चुनौतयिँ हैं और कुछ मुख्य रूप से बाँधों की लंबी उमर के कारण हैं।
- जैसे-जैसे बाँध पुराने होते जाते हैं, उनका डज़िाइन, जल वज्जान और बाकी सब कुछ नवीनतम समझ और प्रथाओं के अनुरूप नहीं

रहता है।

- बाँधों में भारी गाद जमा होती जाती है जिससे इनकी जल धारण क्षमता कम होती जा रही है।

○ बाँध प्रबंधकों पर नरिभरता:

- बाँधों का वनियमन पूरी तरह से व्यक्तिगत बाँध प्रबंधकों पर नरिभर है। डाउनस्ट्रीम जल की आवश्यकता या पहले से मौजूद प्रवाह के प्रकार के संदर्भ में कोई व्यवस्थितिकरण और कोई वास्तविक समझ नहीं है।

○ वभिन्न कारकों पर वचिर नहीं कथिा जाना:

- बाँध सुरक्षा कई कारकों पर नरिभर है जैसे कि भूदृश्य, भूमि उपयोग परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न, संरचनात्मक वशिषताएँ आदि। बाँध की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार द्वारा सभी कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

○ बाँधों की वफिलताएँ:

- उचित बाँध सुरक्षा संस्थागत ढाँचे के अभाव में बाँधों की जाँच, डज़िाइन, नरिमाण, संचालन और रखरखाव में वभिन्न प्रकार की कमियाँ शामिल हो सकती हैं। इस तरह की कमियों से गंभीर घटनाएँ होती हैं और कभी-कभी बाँध टूट जाता है।
- वर्ष 1917 में तगिरा बाँध (मध्य प्रदेश) की वफिलता के साथ बाँधों की वफिलताओं की शुरुआत हुई और अब तक लगभग 40 बड़े बाँधों के वफिल होने की सूचना है। नवंबर 2021 में अन्नामय्या बाँध (आंध्र प्रदेश) की वफिलता का सबसे हालिया मामला 20 लोगों की मौत का कारण बना है।
- सामूहिक रूप से इन वफिलताओं के चलते हज़ारों मौतें और वशिाल आर्थिक नुकसान देखने को मला है।

■ महत्त्व:

○ एकरूपता लाना:

- सरकार चाहती है कि एक वशिष प्रकार के बड़े बाँधों के लिये सभी बाँध मालकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं में एकरूपता हो।

○ सख्त दशिा-नरिदेश प्रदान करता है:

- पानी, राज्य का वशिष है और यह वधियक कसिी भी तरह से राज्य के अधिकार को नहीं छीनता है। वधियक दशिा-नरिदेशों को सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
- इसमें बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पूरी व पोस्ट-मानसून नरिक्षण सहति कई प्रोटोकॉल हैं। हालाँकि अब तक ये प्रोटोकॉल कानूनी रूप से अनविर्य नहीं हैं और संबंधित एजेंसियों (केंद्रीय एवं राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों सहति) के पास इन्हें लागू करने की कोई शक्ति नहीं है।

○ गुणवत्ता सुनिश्चित करना:

- अब तक वभिन्न ठेकेदारों, डज़िाइनरों और योजनाकारों की व्यावसायिक दक्षता का मूल्यांकन कभी नहीं कथिा गया है और यही कारण है कि आज भारत के बाँधों में डज़िाइन की समस्या है। वधियक एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जहाँ नरिमाण और रखरखाव में भाग लेने वाले लोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

○ सुरक्षा:

- बाँधों के क्षतगिरस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है और इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है। वधियक में बाँध सुरक्षा मानकों के नरिमाण का प्रावधान है।

■ चतिा:

○ वसिगत:

- केंद्रीय जल आयोग सभी बाँध परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार होगा। इसे उसी परियोजना (यदि परियोजना वफिल हो जाती है) का ऑडिट करने का भी अधिकार है।
- यह अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश के रूप में कार्य करने जैसा है।

○ क्षतपूरत पर नरित्तर:

- बाँध परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को क्षतपूरत के लिये भुगतान पर वधियक नरित्तर है।

○ संधीय ढाँचे में हस्तक्षेप:

- राज्यों ने आरोप लगाया कि यह असंवैधानिक है इसलिये इसकी जाँच की जानी चाहिये क्योंकि और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। वधियक के कुछ प्रावधान [संधीय ढाँचे](#) में हस्तक्षेप करते हैं।

वधियक की संवैधानिक वैधता

- हालाँकि जल को राज्य सूची की प्रवषिटि-17 में रखा गया है, केंद्र ने संवधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची की प्रवषिटि 56 और प्रवषिटि 97 के साथ कानून प्रस्तुत कथिा है।
 - **राज्य सूची, प्रवषिटि 17:** जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सचिाई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंध, जल भंडारण व जल शक्ति **सूची I की प्रवषिटि 56** के प्रावधानों के अधीन है।
 - **सूची I की प्रवषिटि, 56** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के नयिमन पर कानून बनाने की अनुमति देती है जो इस तरह के वनियमन को सार्वजनिक हति में समीचीन घोषित करती है।
- **अनुच्छेद 246** संसद को संवधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की सूची I में सूचीबद्ध कसिी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
- प्रवषिटि 97 संसद को सूची II या सूची III में सूचीबद्ध कसिी भी अन्य मामले पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जसिमें कर सहति उन सूचियों में से कसिी में भी उल्लेख नहीं कथिा गया है।

आगे की राह

- चूँकि बाँध की सुरक्षा कई बाहरी कारकों पर निर्भर है, इसलिये पर्यावरणविदों और पर्यावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिये **बदलती जलवायु** के साथ पानी के मुद्दे पर सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से विचार करना आवश्यक है।
- राज्य के सचिवाई विभाग और केंद्रीय जल आयोग को मज़बूत करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बाँधों का निरीक्षण संबंधित राज्य की सरकार करे।
- बाँधों के मामले में वफ़िलताओं से बचने के लिये एक नविकारक तंत्र आवश्यक है क्योंकि यदि बाँध निर्माण के उद्देश्यों में वफ़िलता प्राप्त होती है तो कतिनी बड़ी सज़ा क्यों न दी जाए वह जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है।

स्रोत: द हद्दि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dam-safety-bill,-2019>

